

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पूर्वोत्तर भारत में भूमि, विकास और पहचान की राजनीति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

सेंटर फॉर नॉर्थईस्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च (सीएनईएसपीआर), जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा दिनांक 23 - 24 जुलाई 2024 को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा प्रायोजित "पूर्वोत्तर भारत में भूमि, विकास और पहचान की राजनीति" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के समक्ष आने वाले प्रासंगिक विषयों को उजागर करना और इस क्षेत्र में भूमि, विकास और पहचान के बीच जटिल अंतर्संबंध के बारे में नई सोच को बढ़ावा देना था। इस संगोष्ठी में पेपर प्रस्तुतकर्ता पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों सहित कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली से थे।

संगोष्ठी की शुरुआत प्रो मनीषा त्रिपाठी पांडे, मानद निदेशक, सीएनईएसपीआर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा स्वागत भाषण और विषय के परिचय के साथ हुई, जिन्होंने पूर्वोत्तर में भूमि, पहचान और विकास के बीच अंतर्निहित संबंध पर प्रकाश डाला। जामिया के कार्यवाहक कुलपति प्रो. मोहम्मद शकील ने मुख्य अतिथि के रूप में संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने इस क्षेत्र की विविधता को मान्यता दी और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में अकादमिक चर्चा के महत्व पर बल दिया। सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रो. मोहम्मद मुस्लिम खान ने इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया और पूर्वोत्तर भारत के महत्व पर प्रकाश डाला, जो सांस्कृतिक विविधता तथा विविधता की विशेषता वाले कई जातीय समूहों का केंद्र है तब भी वे सभी भावनात्मक रूप से एकजुट हैं।

प्रख्यात विद्वान प्रो. वर्जिनियस ज़ाक्सा ने एक विचारोत्तेजक बीज वक्तव्य दिया और उनके भाषण ने बाद में होने वाली चर्चाओं के लिए माहौल तैयार किया। उन्होंने पूर्वोत्तर की राजनीतिक-प्रशासनिक संरचना पर चर्चा की और पहचान की राजनीति को समझने में ऐतिहासिक संदर्भ के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बताया कि असम के विभाजन के आधार पर इसके निर्माण के बावजूद भी इस क्षेत्र को एकीकृत रूप में देखा जाता है। प्रो. अमरजीत सिंह ने उद्घाटन सत्र में धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस संगोष्ठी में दो दिनों में कुल छह अकादमिक सत्र शामिल थे, जिसमें 25 से अधिक विद्वानों ने पूर्वोत्तर भारत में भूमि मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर शोधपत्र प्रस्तुत किए। पहले दिन "भूमि उपयोग में रुझान और उसका प्रभाव", "विकास परियोजनाएं" और "बुनियादी ढांचे एवं भूमि, भूमि पर राज्य की नीति" पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरे दिन "अंतर-राज्यीय सीमा विवाद और पहचान", "प्रथागत कानून, भूमि और पहचान" पर चर्चा की गई और "भूमि और लैंगिकता" के सत्र के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ। संगोष्ठी प्रस्तुतियों में छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 के तहत स्वदेशी भूमि अधिकारों की सुरक्षा, स्वदेशी समुदायों पर विकास परियोजनाओं के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव, विभिन्न जनजातियों के बीच भूमि विनियोग और असमानताएं, अंतर-राज्यीय सीमा विवादों की जटिलताएं और क्षेत्र भर में विभिन्न जातीय संदर्भों में महिलाओं के भूमि अधिकारों की बदलती गतिशीलता सहित अनेक विषयों को शामिल किया गया। प्रत्येक सत्र के उपरांत विद्वानों और संकाय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों

के साथ संवादात्मक चर्चा हुई। संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के संकाय सदस्यों, शोधार्थियों और छात्रों के साथ-साथ भारत के विभिन्न हिस्सों से अन्य संस्थानों के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया।

संगोष्ठी का समापन प्रो मनीषा टी. पांडे की अध्यक्षता में एक समापन सत्र के साथ हुआ। प्रख्यात विद्वान और मानवविज्ञानी प्रो. सव्यसाची (सेवानिवृत्त) ने समापन भाषण दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भूमि एक त्रि-आयामी इकाई है और यह पहचान की राजनीति की जांच का आधार है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भूमि को केवल दो-आयामी संपत्ति के रूप में देखना सीमित है। यह सीमित दृष्टिकोण व्यक्तियों को स्वयं दो-आयामी बनने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो "मेरी पहचान क्या है और भूमि के संबंध में मैं कौन हूँ" जैसे बुनियादी सवालों को समझने में असमर्थ हैं। उन्होंने पहचान के पांच स्तरों को सामने रखा और जोर देकर कहा कि पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित को समान रूप से संलग्न होना चाहिए और वह भी पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षित को ठीक करने की कोशिश किए बिना। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सीएनईएसपीआर में सहायक प्रोफेसर डॉ. के. कोखो ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस संगोष्ठी ने भूमि और पहचान के जटिल मुद्दों पर चर्चा करके और युद्ध एवं शांति के बीच संवाद के लिए आगे का रास्ता सुझाकर पूर्वोत्तर भारत में युद्धरत जातीय समुदायों को एक अकादमिक मंच पर एक साथ लाने का कार्य किया। यह संगोष्ठी सभी प्रतिभागियों के लिए एक उत्तेजक, उत्पादक और समृद्ध अनुभव वाला साबित हुआ, जिसने पूर्वोत्तर भारत में भूमि के मुद्दों की अधिक व्यापक समझ में योगदान दिया।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया